The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 2 | February 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

महामारी प्रबंधन में प्रिंट मीडिया का समावेशी दृष्टिकोण और जनजातीय समुदायों के लिए विशेष प्रावधान: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 साधना श्रीवास्तव

असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार, मानविकी शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

अभिषेक कुमार

शोध छात्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार मानविकी शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 28-02-2025

Published: 14-03-2025

Keywords:

समावेशी संचार, प्रिंट मीडिया, महामारी प्रबंधन, कोविड-19, जनजातीय समुदाय, सांस्कृतिक संवेदनशीलता

ABSTRACT

महामारी जैसी अप्रत्याशित संकटों में प्रभावी प्रबंधन के लिए समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है,विशेषकर उन हाशिये पर खड़े समुदायों के लिए जिनकी डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सीमित है। कोविड-19 महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में प्रभावी संचार की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। प्रिंट मीडिया ने सूचना के प्रसार, जनजागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस शोध पत्र में महामारी प्रबंधन में प्रिंट मीडिया की समावेशी भूमिका का अध्ययन किया गया हैं, जिसमें भारत के जनजातीय समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐतिहासिक रूप से जनजातीय समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में वंचित रहे हैं जो महामारी के दौरान और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह शोध प्रिंट मीडिया की भूमिका को समझने का प्रयास करेगा, जिसने महामारी के दौरान जनजातीय समुदायों को बहुभाषीय सामग्री, सुलभ जानकारी और सांस्कृतिक रूप

से उपयुक्त संदेशों के माध्यम से जोड़ा। इस शोध कार्य से पता चलेगा कि कैसे प्रिंट मीडिया ने स्वच्छता, सामाजिक दूरी और वैक्सीनेशन जैसे गंभीर विषयों पर जागरूकता बढ़ाई और सूचना की खाई को पाटने में मदद की। इसमें जनजातीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई सामग्री का विश्लेषण शामिल होगा जिससे समुदायों ने जानकारी को समझकर उस पर अमल किया। यह शोध द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। महामारी के दौरान प्रकाशित प्रिंट सामग्री का अध्ययन करेगा। इसके आधार पर नीतिगत सुझाव दिए जाएंगे ताकि भविष्य में प्रिंट मीडिया महामारी प्रबंधन का अभिन्न अंग बन सके। यह शोध स्वास्थ्य सेवाओं में समानता सुनिश्चित करने और हाशिए पर खड़े वर्गों की जरूरतों को प्राथमिकता देने में सहायक होगा। यह शोध भविष्य के स्वास्थ्य संकटों के लिए एक उपयोगी मॉडल प्रदान कर सकता है, जिसमें समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके।समावेशी मीडिया दृष्टिकोण को समझना न केवल महामारी प्रबंधन की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक होगा बल्कि यह स्वास्थ्य सेवाओं में समानता सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक कदम होगा।

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.15030114

प्रस्तावना

कोविड-19 महामारी ने संकट संचार में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। टेलीविजन और डिजिटल मीडिया ने तत्काल जानकारी प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई जिससे लोग स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और सरकारी नीतियों से अपडेट हो सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने वास्तविक समय में व्यापक संचार और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य किया और गलत सूचना का मुकाबला किया। प्रिंट मीडिया हालांकि धीमा था लेकिन इसने जन

जागरूकता और विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से उन समुदायों तक पहुँचने में जिनके पास इंटरनेट की सीमित पहुँच थी। मीडिया ने न केवल लोगों को सही जानकारी दी बल्कि टीकाकरण अभियान और निवारक उपायों को बढ़ावा दिया। कुल मिलाकर मीडिया ने महामारी के दौरान प्रभावी संचार और प्रतिक्रिया रणनीतियों को संचालित किया जो महामारी नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों में महत्वपूर्ण थे।

आदिवासी समुदाय जो अक्सर दूरदराज या एकाकी इलाकों में रहते हैं महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, जानकारी और संसाधनों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं। इन समुदायों को खराब सड़कें, सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं और विश्वसनीय संचार नेटवर्क जैसी अपर्याप्त बुनियादी संरचनाओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक और सामाजिक कारक जैसे गरीबी और शिक्षा की कमी इन समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। सांस्कृतिक अवरोध भी स्वास्थ्य जानकारी के प्रभावी प्रसार में बाधक होते हैं क्योंकि पारंपरिक विश्वास आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से टकरा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप इन समुदायों की विशिष्ट जरूरतें अक्सर पूरी नहीं हो पातीं जिससे महामारी जैसी स्वास्थ्य संकटों से निपटने में अधिक कठिनाई होती है।

अध्ययन की सार्थकता

यह अध्ययन महामारी प्रबंधन में प्रिंट मीडिया की भूमिका का विश्लेषण करता है,विशेष रूप से आदिवासी समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके समावेशी दृष्टिकोण पर। इस शोध कार्य से यह पता चलता है कि स्वास्थ्य संकटों के दौरान मीडिया कैसे समयबद्ध, सटीक और सुलभ जानकारी प्रदान कर सकता है। खासकर हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए। यह अध्ययन आदिवासी समुदायों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों, समावेशी मीडिया के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों पर प्रभाव और नीतियों तथा संचार रणनीतियों में मौजूद अंतराल को उजागर करता है। यह अध्ययन मीडिया अध्ययन, संकट संचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य में समावेशी और प्रभावी महामारी प्रबंधन के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

शोध पद्धति

यह शोध पत्र कोविड- 19 महामारी के दौरान प्रिंट मीडिया द्वारा जनजातीय समुदायों से संबंधित मुद्दों की कवरेज का गुणात्मक विश्लेषण करता है। अनुसंधान डिजाइन में प्रिंट मीडिया सामग्री जैसे रिपोर्ट, लेख और विशेष संस्करणों का अध्ययन शामिल है। यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया।

शोध उद्देश्य

1.महामारी के दौरान संचार में प्रिंट मीडिया की भूमिका का विश्लेषण करना।

2. प्रिंट मीडिया द्वारा जनजातीय समुदायों के लिए उठाए गए विशेष कदमों की जांच करना।

3. भविष्य में स्वास्थ्य संकटों में प्रिंट मीडिया के उपयोग के लिए सुझाव देना।

साहित्य की समीक्षा

काशी(2021) यह लेख भारत में आदिवासी जनसंख्या की परिस्थितियों, सरकार द्वारा उठाए गए उपायों और स्थानीय संगठनों की भूमिका का आलोचनात्मक समीक्षा करने का प्रयास करता है जो आदिवासी लोगों को महामारी के दौरान स्थिरता बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान आदिवासी युवाओं पर प्रकाशित कार्यों की अनुपलब्धता लेख के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय थी। भारत में आदिवासी युवाओं की कमजोर स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन मंत्रालय की आदिवासी मामलों और अन्य सरकारी रिपोर्टों में उपलब्ध माध्यमिक डेटा पर आधारित है। आदिवासी लोगों पर महामारी के प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कई मामलों की जानकारी समाचार रिपोर्टों और ब्लॉग पोस्टों से एकत्र की गई है, और इसे उपलब्ध सरकारी रिपोर्टों के संदर्भ में एकत्रित करके मूल्यांकित किया गयाभारत में आदिवासी युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और कलंक जैसी असमानताओं का सामना करना पड़ा था। महामारी ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया था, जिसमें पुरुषों को नौकरियों का नुकसान और महिलाओं को आर्थिक समस्याएं और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। सरकार की योजनाएं पर्याप्त नहीं थी और ैभ्ळे और सहकारी संगठनों की मदद के बिना इन समस्याओं का सामना करना मुश्किल था।

मैट्स एरिक्सन (2018) यह अध्ययन 2004 से 2017 के बीच प्रकाशित 104 सहकर्मी-समीक्षित लेखों और सम्मेलन पत्रों से प्राप्त सोशल मीडिया संकट संचार के लिए प्रभावी सलाह की जांच करता है। पांच प्रमुख पाठ पहचाने गए हैं ।संवाद के लिए सोशल मीडिया का उपयोग और उपयुक्त संदेश भेजना, संकट-पूर्व तैयारी और सोशल मीडिया तर्क को समझना, सोशल मीडिया निगरानी का उपयोग करना, पारंपरिक मीडिया को प्राथमिकता देना और संकट संचार में सोशल मीडिया का रणनीतिक रूप से समावेश। यह अध्ययन मुख्यतः अमेरिका-केंद्रित और ट्विटर-आधारित शोध पर आधारित है। भविष्य में विविध प्लेटफॉर्म और वैश्विक संदर्भों पर अधिक शोध की आवश्यकता है। यह अध्ययन संकट प्रबंधन और संकट संचार पर शोध की गहन और व्यवस्थित समीक्षा करता है। यह गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का उपयोग करते हुए तीन चरणोंकृस्रोत पहचान, नमूना चयन और व्यवस्थित विश्लेषण के माध्यम से संकट संचार और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है।यह अध्ययन वैश्विक सोशल मीडिया संकट संचार के लिए पांच मुख्य पाठों को पहचानता है- संवाद का उपयोग करना, सही संदेश और समय चुनना, संकट से पहले योजना बनाना, सोशल मीडिया निगरानी करना, और पारंपरिक मीडिया को भी महत्व देना। यह अमेरिकी आधारित अध्ययन पर निर्भरता की आलोचना करता है और वैश्विक शोध की आवश्यकता को बताता है।

ब्रिटनी हॉप्ट(2021) यह शोधपत्र आपदा प्रबंधन में संकट संचार रणनीतियों के उपयोग और उन पर स्थितिजन्य संकट संचार सिद्धांत के प्रभाव को समझाता है। यह स्थानीय जरूरतों और संकट के प्रकार के अनुसार रणनीतियों को ढालने पर जोर देता है। सर्वेक्षण और विश्लेषण के जरिए लचीलापन बढ़ाने और बेहतर प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।यह अध्ययन संकट संचार रणनीतियों, सामुदायिक आवश्यकताओं और लचीलापन के बीच संबंध की जांच करता है जो ैब्ब्ज् सिद्धांत पर आधारित है। इसमें जिला स्तर पर आपातकालीन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है जहां आपातकालीन प्रबंधकों की जानकारी छानने, पैटर्न पहचानने और संकट प्रबंधन में प्रभावी निर्णय लेने की अनुकूलन क्षमता को प्रमुखता दी गई है।

यह अध्ययन आपदा प्रबंधन में संकट संचार रणनीतियों पर केंद्रित है, जिसमें आपदा प्रबंधकों की महत्वपूर्ण भूमिका, कार्यान्वयन में चुनौतियाँ और हितधारकों के सहयोग, अनुकूलन एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता को उजागर किया गया है। मुख्य बाधाओं में उदासीनता, भूमिकाओं की जटिलता और नीतिगत निर्णय प्रक्रिया में प्रबंधकों का बहिष्कार

शामिल है। प्रभावी रणनीतियाँ विश्वास, पारदर्शिता, सामुदायिक-केंद्रित दृष्टिकोण और प्रबंधकों को रणनीति विकास व क्रियान्वयन में सम्मिलित करने पर निर्भर करती हैं।

अगोरामूर्ति,जे.एच.एस.यू. (2021). कोविड- 19 महामारी ने दुनियाभर में आदिवासी जनजातियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है जिसमें ब्राजील के आदिवासी और पेरू की नाहुआ जनजाति शामिल हैं। भारत के 10 करोड़ आदिवासियों पर इसके प्रभाव से संबंधित जानकारी बेहद कम है जिससे इन कमजोर समूहों पर महामारी के अनदेखे प्रभाव उजागर होते हैं।भारत में 1950 में आरक्षण प्रणाली शुरू हुई ताकि निम्न जातियों के वंचित वर्गों को ऊपर उठाया जा सके, लेकिन जातिगत भेदभाव अब भी जारी है। 8ः जनसंख्या वाले आदिवासी समुदाय गरीबी, पलायन, और खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। वनों से प्राप्त 20 अरब डॉलर की आय का बड़ा हिस्सा बिचैलियों के पास चला जाता है, जिससे उनकी समस्याएँ बढ़ रही हैं।कोविड-19 महामारी ने भारत की आदिवासी जनजातियों पर गहरा प्रभाव डाला, जो देश की जनसंख्या का 8ः हैं और गरीबी व सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझते हैं। लॉकडाउन ने खाद्य असुरक्षा और प्रवासन संकट को बढ़ा दिया, क्योंकि कई लोग रोजगार खोकर दूरदराज के गांवों में लौटने के लिए संघर्ष करते रहे। ओडिशा और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों सहित कमजोर समूह बाहरी संपर्क के कारण संक्रमण का शिकार हुए। ऐतिहासिक महामारियों ने इन जनजातियों को बुरी तरह प्रभावित किया है, और कोविड-19 ने उनकी संवेदनशीलता को उजागर किया है। पारंपरिक जीवनशैली पर निर्भर इन समूहों के लिए आपातकालीन उपाय आवश्यक हैं।भारत की आदिवासी जनजातियां जो पहले से ही गरीब और कमजोर थी ब्व्टप्क्-19 से बहुत प्रभावित हुईं। महामारी के कारण उनकी आजीविका खत्म हो गई।खाने की कमी हो गई और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाईं। इसके समाधान के लिए उनकी पारंपरिक जीवनशैली का सम्मान करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी मदद और विशेष बजट का प्रबंध करना जरूरी है।

जे.अम्बागुडियां(2022). इस लेख में यह बताया गया है कि भारत की आदिवासी समुदायों को कोविड-19 महामारी के दौरान ऐतिहासिक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर होने के कारण अधिक जोखिम का सामना करना पड़ा। यह उनके संसाधनों की कमी, संरचनात्मक समर्थन की अनुपस्थिति और असमान अवसरों के कारण उनकी बढ़ी हुई संवेदनशीलताओं को उजागर करता है।

मेघानी, ए., शर्मा, एम., सिंह, टी., घोष दस्तीदार, एस., धवन, वी., कनागत, एन., गुप्ता, ए., भटनागर, ए., सिंह, के., शियरर, जे.सी., और सोनी, जी.के.(2024) मोमेंटम परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ और झारखंड के जनजातीय समुदायों में कोविड -19 टीकाकरण की दर को बढ़ाना था। मुख्य हस्तक्षेपों में लक्षित परामर्श, सामुदायिक आयोजन और लचीले टीकाकरण कार्यक्रम शामिल थे। सफलता सामुदायिक नेताओं की भागीदारी, अनुकूलित संदेश और निरंतर वित्तीय और राजनीतिक समर्थन पर निर्भर थी।यह केस अध्ययन झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों में कोविड -19 वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए मोमेंटम परियोजना की रणनीति का मूल्यांकन करता है। प्रमुख हस्तक्षेपों में समुदाय के नेताओं के साथ साझेदारी, घर-घर जाकर जागरूकता फैलाना और सामुदायिक सभाओं का आयोजन शामिल था। इस परियोजना ने स्थानीय और सांस्कृतिक रूप से अनुकूल दृष्टिकोणों के माध्यम से जागरूकता और वैक्सीनेशन कवरेज में सफलता हासिल की।

यह परियोजना समुदाय के नेताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और दूतों के साथ सहयोग करके जनजातीय समुदायों में टीकाकरण जागरूकता और अपटेक को बढ़ाने में सफल रही। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त संचार और समुदाय की प्रतिक्रिया ने चुनौतियों को पार करने में मदद की। ये रणनीतियाँ भविष्य की स्वास्थ्य पहलों के लिए एक मॉडल प्रदान करती हैं।

रमेश, आर.एम., अरुलदास, के., मार्कोनी, एस.डी., जनराज, वी., रोज, ए., जॉन, एस.एम., मूर्ति, एम., मुलियिल, जे., सरवनकुमार, पी.के., अजामपुर, एस.एस.आर., और सिंधु, के.एन. (2022). यह अध्ययन तमिलनाडु के ग्रामीण और आदिवासी परिवारों पर लॉकडाउन के प्रभावों को समझने के लिए किया गया था। इसके लिए एक मिश्रित तरीका अपनाया गया, जिसमें एक प्रश्नावली और फोकस समूह चर्चा शामिल थी। सर्वे जुलाई और अगस्त 2020 में किया गया, जब लॉकडाउन के प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा था। यह अध्ययन तमिरी (वेल्लोर जिला) और जवाधू पहाड़ियों (तिरुवन्नामलाई जिला) में किया गया, जिनकी जनगणना 2017 में हुई थी।तमिरी में 219 गाँव हैं और यहाँ की जनसंख्या 105,691 है। यहाँ चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 25 उप-केंद्र हैं। अधिकांश लोग दैनिक मजदूरी (42), कृषि (20), या कौशलयुक्त काम (15) करते हैं। करीब 18 लोग अनपढ़ हैं, और 9 गरीब वर्ग से आते हैं। जवाधू पहाड़ी क्षेत्र में 390 गाँव हैं और यहाँ की जनसंख्या 51,999 है। यहाँ के लोग ज्यादातर कृषि कार्य (88)

करते हैं, और कुछ लोग अन्य जिलों में काम के लिए जाते हैं। आधे लोग अनपढ़ हैं, और 58 लोग गरीब वर्ग से हैं। दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याएँ हैं।

भारत में लॉकडाउन ने कोविड -19 के फैलाव को रोकने में मदद की, लेकिन इसने ग्रामीण और आदिवासी परिवारों पर स्वास्थ्य, पैसे, शिक्षा और कामकाजी जीवन पर बुरा असर डाला। बेरोजगारी और संपत्ति की हानि जैसे नुकसान को देखते हुए, कमजोर परिवारों के लिए खास मदद की जरूरत है।

इंडियन एक्सप्रेस (2020) ओडिशा में आदिम जनजातियों के छह सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिससे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह ख्पीवींटीजीस, की संवेदनशीलता पर चिंता जताई जा रही है। इन जनजातियों के लोग सामुदायिक जीवन जीते हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति अत्यधिक खराब है जैसे कि कुपोषण, निरक्षरता और सीमित स्वास्थ्य सेवाएं। संक्रमण का स्रोत स्पष्ट नहीं था लेकिन यह संभावना था कि दूसरे स्थानों से आए लोग संक्रमण का कारण बने थे पीवींटीजीसे के विकास को लेकर सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है ताकि इन जनजातियों को महामारी जैसी समस्याओं से बचाया जा सके।

पीआईबी (अप्रैल 2020).यह लेख कोविड -19 के प्रति जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को रेखांकित करता है। इसमें सरकारी आदेशों के अनुसार स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आवाजाही पर प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने की बात की गई है। इसके अलावा लंबित राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्तियों की प्रक्रिया पूरी करना, लाभार्थियों को छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्तियों से संबंधित अनुरोधों को प्राथमिकता देना और यूनिसेफ के साथ मिलकर कोविड -19 के बारे में जागरूकता फैलाना जैसी पहलें की गई हैं। साथ ही मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन राहत कार्यों में लगे हुए हैं और किसी भी समस्या का समाधान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया गया था।

लाइव हिंदुस्तान (18 मई 2021).कोविड-19 महामारी ओडिशा के भीतरी इलाकों में कम से कम 61 कमजोर आदिवासी समूह में फैल रहा था। अधिकारियों ने बताया कि संक्रमण के बाद भी डोगरिया कोंध आदिवासी टेस्टिंग का विरोध कर रहे थे। इस जनजाति के 19 लोगों के संक्रमित होने के बाद भी टेस्टिंग के लिए नियामगिरी पहाड़ियों की

तलहटी में परसली में चिकित्सा शिविर स्थापित किया गया था लेकिन एक भी आदिवासी कोरोना टेस्टिंग के लिए नहीं आया था।

रावत (2 जून 2021). यह लेख कोविड-19 महामारी के सामाजिक रिश्तों और मानव संपर्क पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। सामाजिक दूरी के नियमों ने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को तोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप एकाकीपन और डर का अहसास हुआ। महामारी ने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर कर दिया। त्यौहार, मिलन समारोह और रीति-रिवाज जो पहले एकजुटता के अवसर होते थे अब संक्रमण के डर से संकोचपूर्ण हो गए हैं। लेख में सामूहिक भावना की हानि और यह उम्मीद जताई गई है कि महामारी के बाद मानवता अपने सामाजिक संबंधों को फिर से पुनर्निर्मित करेगी।

इंगेज (2021). इस लेख में कोविड-19 महामारी के दौरान आदिवासी समुदायों पर राज्य की उपेक्षा के प्रभाव को दर्शाया गया है। महामारी ने इन समुदायों की पहले से कमजोर स्थिति को और बढ़ा दिया, जिससे उनके रोजगार के अवसर खत्म हो गए और आय स्रोतों में रुकावट आई। लॉकडाउन के कारण आदिवासी मजदूरों और विक्रेताओं को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेख में सरकार से इन समुदायों के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है

विश्लेषण और चर्चा

कोविड-19 महामारी के दौरान प्रिंट मीडिया ने सुरक्षा उपायों, टीकाकरण जानकारी और स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आदिवासी क्षेत्रों में जानकारी पहुँचाने में कई चुनौतियाँ थीं जैसे सीमित बुनियादी ढांचा, कम साक्षरता दर और भाषा की बाधाएँ। अधिकांश सामग्री हिंदी या अंग्रेजी में थी जिससे स्थानीय बोलियों में संवाद की खाई उत्पन्न हुई। इन समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय भाषाओं में सामग्री का वितरण, स्थानीय नेताओं के साथ सहयोग और रेडियो जैसे ऑडियो-विजुअल माध्यमों का उपयोग किया गया। हालांकि आदिवासी इलाकों में जानकारी की आपूर्ति में कमी रही और गलत जानकारी भी फैलने लगी।सरकारी एजेंसियों और मीडिया के

सहयोग से आदिवासी क्षेत्रों में टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुँचाने में सुधार हुआ। भविष्य में प्रिंट मीडिया को स्थानीयकृत सामग्री, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और भाषाई रूप से उपयुक्त संदेशों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्थानीय नेताओं के साथ सहयोग और समावेशी रिपोर्टिंग से आदिवासी समुदायों को स्वास्थ्य पहलुओं में बेहतर समर्थन मिल सकता है। आदिवासी समुदायों को कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। भाषा की समस्या, कम पढ़ाई-लिखाई और दूर-दराज के इलाकों में मीडिया की पहुँच की कमी इन समुदायों के लिए स्वास्थ्य संदेशों को समझना मुश्किल बना दिया था। इसके अलावा सांस्कृतिक भिन्नताएँ भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को समझने में रुकावट डाल रही थी। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समावेशी तरीका अपनाना जरूरी है। इसमें स्थानीय भाषाओं का उपयोग, सामुदायिक रेडियो जैसे पारंपरिक मीडिया के रूपों का सहारा और आदिवासी समुदाय की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य संदेशों को बदलना शामिल है। यह भी जरूरी है कि आदिवासी लोगों को संचार प्रक्रिया में शामिल किया जाए और सरकारों, एनजीओ और मीडिया के साथ मिलकर काम किया जाए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी तक पहुँचे। इस तरीके से सभी को स्वास्थ्य जानकारी मिल सकती है और महामारी से निपटने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

प्रिंट मीडिया महामारी प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों, जिसमें जनजातीय समुदाय के लिए विश्वसनीय और सुलभ जानकारी प्रदान करता है। यह सही स्वास्थ्य दिशानिर्देशों, बचाव उपायों और टीकाकरण जानकारी का तेजी से प्रसार सुनिश्चित करता है जिससे गलत सूचना और भय को कम किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया का लाभ यह है कि यह उन क्षेत्रों तक पहुंचता है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सीमित होती है और इसे स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है जिससे विश्वास और समझ बनती है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रिंट मीडिया ने सूचनाओं के प्रसार में अहम भूमिका निभाई, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में इसकी पहुंच सीमित रही। स्थानीय भाषा और संदर्भ की कमी, साक्षरता दर में कमी, और फर्जी खबरों के प्रसार ने जनजातीय समुदायों के लिए चुनौतियां बढ़ाईं। कुछ प्रिंट मीडिया ने जनजातीय मुद्दों को उजागर कर सकारात्मक प्रभाव डाला, लेकिन आर्थिक और तकनीकी सीमाओं ने जानकारी के प्रसार में बाधा

उत्पन्न की। महामारी प्रबंधन में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिक समावेशी और संवेदनशील होना चाहिए।

जनजातीय समुदायों के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है जिसमें उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं और भौगोलिक एकांत को पहचाना जाए। प्रिंट मीडिया को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नेताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल करना चाहिए कि संदेश समझे जाएं और अच्छी तरह से प्राप्त हों। प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सामग्रियों को विभिन्न भाषाओं और प्रारूपों में वितरित किया जाना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक प्रतीकों का उपयोग किया जाना चाहिए।मुख्य नीति सिफारिशों में समायोजित संदेशों का विकास, समुदाय नेताओं के साथ सहयोग, दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित करना और जागरूकता अभियानों को महामारी के तुरंत बाद भी जारी रखना शामिल है। सरकारों को इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए संसाधन आवंटित करने चाहिए ताकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक प्रिंट मीडिया के माध्यम से आवश्यक स्वास्थ्य जानकारी पहुंचे। इस समावेशी दृष्टिकोण से सभी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सुनिश्चित होती है और महामारी के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया मिलती है।

सन्दर्भ सूची:

Meghani, A., Sharma, M., Singh, T., Dastidar, S. G., Dhawan, V., Kanagat, N., Gupta, A., Bhatnagar, A., Singh, K., Shearer, J. C., & Soni, G. K. (2024). Enhancing COVID-19 vaccine uptake among tribal communities: A case study on program implementation experiences from Jharkhand and Chhattisgarh States, India. Vaccines, 12(5), 463. https://doi.org/10.3390/vaccines12050463

Eswarappa, K., & Saha, A. (2021). Pushed to the margins: The crisis among tribal youth in India during COVID-19. Critical Sociology, 47(4–5), 641–655. https://doi.org/10.1177/0896920520980111

Haupt, B. (2021). The use of crisis communication strategies in emergency management. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 18(2), 125–150.

Ambagudia, J. (2022). Tribes, COVID-19 and the state in India. SAGE Journals, 59(2). https://doi.org/10.1177/00219096221117073

Mats Eriksson (2018) Lessons for Crisis Communication on Social Media: A Systematic Review of What Research Tells the Practice, International Journal of Strategic Communication, 12:5, 526-551. https://doi.org/10.1080/1553118X.2018.1510405

Ramesh, R. M., Aruldas, K., Marconi, S. D., Janagaraj, V., Rose, A., John, S. M., Moorthy, M., Muliyil, J., Saravanakumar, P. K., Ajjampur, S. S. R., & Sindhu, K. N. (2022). Impact of the COVID-19 national lockdown on a rural and tribal population of Tamil Nadu, Southern India: A mixed-methods survey. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 106(5), 1498–1506.

https://www.drishtiias.com/hindi/pdf/1677707317.pdf

https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1616661

https://www.livehindustan.com/national/story-corona-started-spreading-among-tribals-dongria-kondh-tribe-not-ready-for-testing-4039435.html

https://www.amarujala.com/columns/blog/coronavirus-virus-pandemic-and-human-society

https://www.epw.in/engage/article/covid-19-and-tribal-communities-how-state-neglect